

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूज़

भोपाल, शनिवार 27 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2025

भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित

वर्ष- 12

अंक-60

पृष्ठ- 8

मूल्य- रु. 5/-

नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बढ़ाने के लिए राज्यों पर केंद्र का दबाव: मंत्री प्रह्लाद जोशी

44 GW अन बिकी ऊर्जा को समाप्त करने की पहल, 2030 तक 500 GW लक्ष्य पर जोर

इद दिल्ली: भारत सरकार नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से राज्यों को स्वच्छ ऊर्जा की अधिक खरीद के लिए प्रोत्साहित कर रही है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कई राज्य-संचालित बिजली कंपनियां खरीद में देरी कर रही हैं, जिससे 44 गीगावाट (जीडब्ल्यू) से अधिक स्वच्छ ऊर्जा अन बिकी पड़ी हुई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के ऊर्जा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, "राज्यों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो बिजली कीमतों में और गिरावट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्द ही दूसरी दौर की वार्ता होगी।"

जोशी ने बताया कि कम मांग के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन केंद्र सरकार 2030 तक 500 GW गैर-जीवाशम ईंधन क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें सौर ऊर्जा में 292 GW शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य बिजली वितरण

कंपनियों (डिस्कॉम) को पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि नवीकरणीय परियोजनाओं को गति मिल सके।

मंत्री ने जीएसटी दरों में कमी का भी जिक्र किया, जो लेवलाइज़ रिन्यूएबल टैरिफ को कम करेगी और डिस्कॉम के लिए बिजली खरीद की लागत घटाएगी। इससे देशभर में प्रतिवर्ष 2,000-3,000 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इसके अलावा, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत 20 लाख घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।

जोशी ने निजी निवेशकों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति एक राष्ट्रीय मिशन है। वैश्विक स्तर पर भारत नवीकरणीय क्षमता वृद्धि में शीर्ष तीन देशों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगी, बल्कि आर्थिक



विकास को भी बढ़ावा देगी। केंद्र की यह रणनीति राज्यों के साथ सहयोग से 300 GW नवीकरणीय क्षमता जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी।

नवीकरणीय ऊर्जा से सब्सिडी बोझ समाप्त करने का लक्ष्य: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव

तीन वर्षों में 18,000 करोड़ की बचत का सपना, सौर-स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और न्यूक्लियर पर फोकस

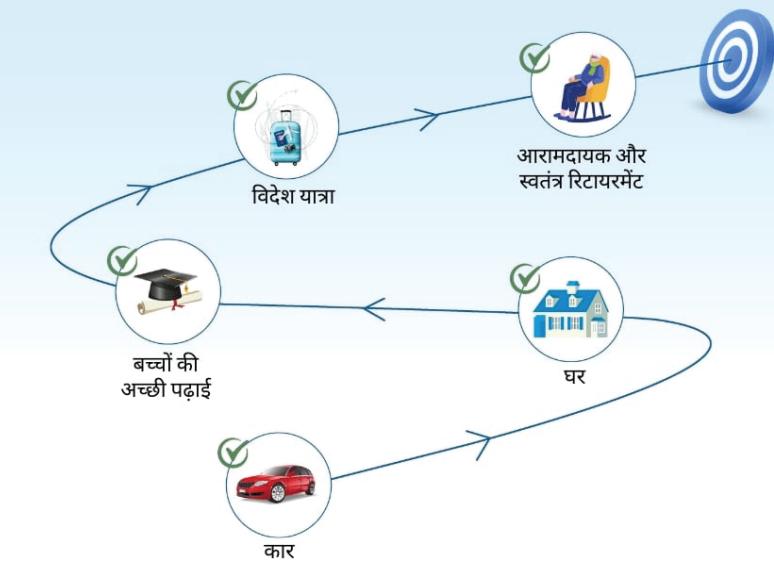
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नवीकरणीय ऊर्जा को राज्य की ऊर्जा सब्सिडी बोझ समाप्त करने की कुंजी बताया है। किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती, विश्वसनीय और नियमित हरित बिजली उपलब्ध कराने के लिए सौर, पवन और स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में सब्सिडी का बोझ पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वर्तमान में किसानों को दिए जाने वाले ऊर्जा सब्सिडी का खर्च प्रतिवर्ष लगभग 18,000 करोड़ रुपये है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, "नई और नवीन समाधानों पर निर्भर रहते हुए हम इन प्रोजेक्ट्स का समर्थन कर रहे हैं। मोरेना में सौर-सह-स्टोरेज सुविधा ने रिकॉर्ड कम टैरिफ हासिल किया है, जो 24x7 हरित बिजली आपूर्ति का आधार बनेगा।" राज्य सरकार डिसेंट्रलाइज़ रिन्यूएबल पावर पर भी काम कर रही है, जहां छोटे-छोटे भूखंडों पर 2-10 मेगावाट के सौर प्रोजेक्ट्स स्थापित किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स सबस्टेशनों से जुड़े होने से ऊर्जा हानि कम करेंगे और क्षमता का कुशल उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा, राज्य न्यूक्लियर ऊर्जा के अवसरों का लाभ उठाने की योजना बना रहा है। चुटका में एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जबकि नीमच में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। यादव ने कहा, "केंद्र के 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर क्षमता के लक्ष्य का फायदा उठाना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त भूमि बैंक है।" उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रिन्यूएबल प्रोजेक्ट भी विकसित हो रहा है, जहां प्रत्येक राज्य को छह-छह महीने बिजली आपूर्ति होगी, क्योंकि उनकी मांग चक्र पूरक है।

मुख्यमंत्री ने निजी निवेशकों को आमंत्रित किया, कहा कि मध्य प्रदेश रिन्यूएबल सेक्टर में आकर्षक अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ सौर वॉटर पंप्स की स्थापना से किसानों को लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल न केवल सब्सिडी कम करेगी, बल्कि राज्य की स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाएगी, जिससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

जीवन के लक्ष्य जो हासिल करने लायक हैं



इन सभी को हासिल करना संभव है

SIP के माध्यम से

अपने Bucket List के items को पूरा करने के लिए मुझसे संपर्क करें।

मूल्यांकित फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले कृपया सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

+(91)7389912025

visionadvisorymkt@gmail.com



ऑटोमोबाइल कंपनियों में बुकिंग में उछाल, जीएसटी दरों में कटौती ने बढ़ाई मांग

सस्ती कारों की बढ़ती मांग से बाजार में उत्साह

भोपाल: हाल ही में सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में नई जाने फूंक दी है। प्रमुख कार निर्माता कंपनियों ने बताया कि इस कटौती के बाद कारों की बुकिंग में 20-30% तक का उछाल देखा गया है। विशेष रूप से कॉम्पैक्ट और मिड-साइज सेडान कारों की मांग में तेजी आई है, क्योंकि ये वाहन अब पहले से कहीं अधिक किफायती हो गए हैं। मारुति सुजुकी, हुंडई और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने पिछले महीने की तुलना में बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी दरों में 2-5% की कमी ने उपभोक्ताओं का कहना है कि जीएसटी दरों में 2-5% की कमी ने उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाया है, खासकर मध्यम वर्ग के बीच, जो लंबे समय से कार

खरीदने की योजना टाल रहे थे।

इसके अलावा, त्योहारी सीजन के नजदीक आने से भी बाजार में उत्साह है। डीलरशिप पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है, और कई कंपनियों ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की घोषणा की है ताकि मांग को पूरा किया जा सके। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने आपूर्ति श्रृंखला में संभावित चुनौतियों की चेतावनी दी है, जो इस उछाल को प्रभावित कर सकती हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, जो हाल के वर्षों में आर्थिक मंदी और महामारी के प्रभावों से जूझ रहा था। जीएसटी कटौती के इस कदम से न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होगा, बल्कि यह अर्थव्यवस्था को भी गति दे सकता है।



Ola Electric Ignites Festive Frenzy with Muhurat Mahotsav, prices starting from ₹49,999/-

Nine-Day Flash Sale Spotlights S1 X and Roadster X, Limited Units to Drive EV Adoption in Urban India

Bengaluru: Ola Electric Mobility has supercharged the festive season with the launch of its "Ola Celebrates India" campaign, featuring the much-anticipated Muhurat Mahotsav a nine-day extravaganza offering electric scooters and motorcycles at unprecedented prices starting from ₹49,999. Kicking off on September 23, the event targets budget-conscious buyers eager to embrace green mobility amid rising fuel costs and environmental awareness.

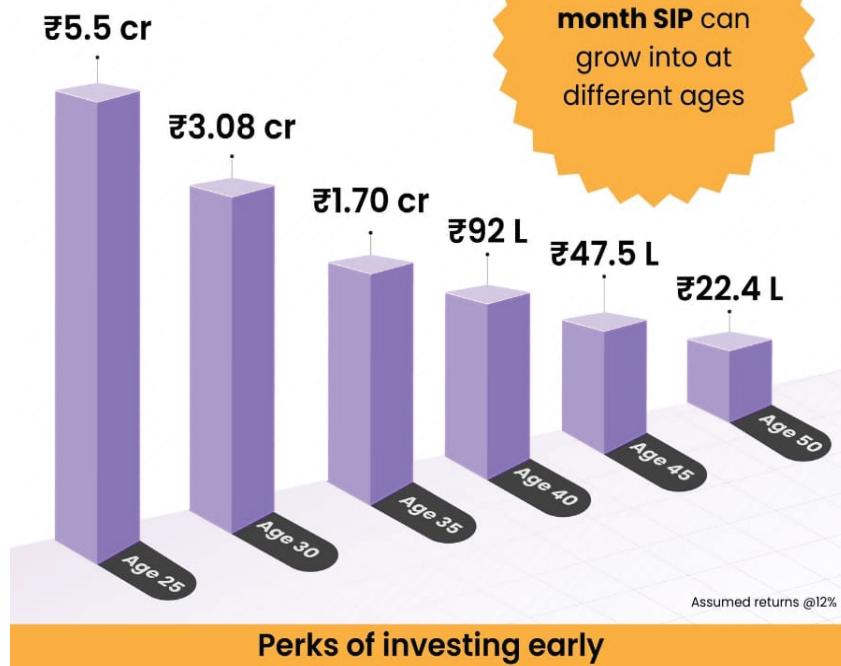
Under the spotlight are the entry-level S1 X (2kWh) scooter and Roadster X (2.5kWh) motorcycle, both slashed to ₹49,999—a steep discount from their regular tags, making them accessible for urban commuters seeking affordable, zero-emission rides. For those craving more power, the premium S1 Pro+ (5.2kWh) and Roadster X+ (9.1kWh), powered by Ola's innovative 4680 Bharat Cell battery packs, are available at ₹99,999 during limited daily slots. These models promise enhanced range and faster charging, aligning with India's push towards sustainable transport.

The sale operates on a first-come, first-served basis, with exclusive Muhurat time-slots announced each morning on Ola's social media channels. Limited units ensure high demand and quick sell-outs, echoing the frenzy of e-commerce flash deals but rooted in cultural festivities. "The Muhurat Mahotsav isn't just about unbeatable prices; it's about democratizing world-class EVs for every Indian home, blending our rich heritage with cutting-edge innovation," said an Ola Electric spokesperson.

This strategic move comes as Ola eyes a bumper festive quarter, following its recent rollout of Gen 3 S1 scooters and Roadster series. With mass-market variants like the S1 X+ (4kWh) at ₹81,999 to ₹1,11,999 and Roadster X up to ₹1,27,499, the lineup caters to diverse needs. Analysts predict the campaign could boost Ola's market share in the ₹10,000-crore EV two-wheeler segment, where it already leads with over 30% penetration.

As Navratri approaches, Ola's initiative not only fuels sales but also accelerates India's EV revolution, potentially reducing urban emissions by thousands of tons annually. Early birds are already queuing up will you join the charge.

Want to see how your portfolio will look **at 60?**



What ₹10,000/
month SIP can
grow into at
different ages

Perks of investing early

I can help you plan your finances

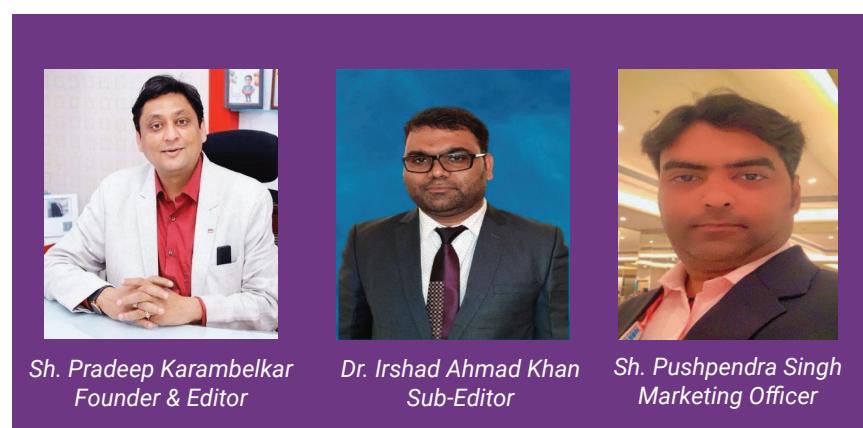
Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the documents carefully before investing.



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

Call (+91)7389912025 | Email: visionadvisorymkt@gmail.com



Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

GST 2.0: The Economic Catalyst India Needs, How the Revised 2025 GST Will Energize Money Flow & Amplify Sales

The Indian government rolled out a landmark revision to the Goods and Services Tax (GST), often dubbed "GST 2.0". With a simplified two-slab system (5 % and 18 %), elimination of certain slabs, and special rates for luxury/sin goods, the reform is designed to free up money in the system, drive consumption, and revive business growth.

Here's how the revised GST is expected to bolster the Indian economy especially by injecting liquidity, lifting sales, and redistributing money through the system.

1. More disposable income: money stays in people's pockets

By slashing tax rates on hundreds of essential goods, household staples, electronics, and consumer durables, GST 2.0 increases the real purchasing power of consumers.

For example, goods earlier taxed at 12 % have shifted largely to 5 %, and many goods from 28 % now bear 18 %.

When consumers spend less tax and more acquisition cost, they tend to buy more boosting demand across sectors. This extra liquidity circulates quickly: more demand more production more incomes further demand. That multiplier effect is central to how modern macroeconomics works.

2. Liquidity in the system & formalisation of business

Because the tax structure is simpler and rate mismatches (inverted duty structures) are being corrected, businesses recover input credits more smoothly.

That improves working capital more cash remains within firms rather than being stuck in tax credit disputes.

Also, streamlined digital compliance (pre-filled returns, faster refunds, clearer classification) reduces compliance friction, encouraging smaller firms to enter the formal economy.

As more business shifts into the formal sector, tax base and transparency grow supporting sustainable revenue in the long run.

3. Surge in sales: Demand Unleashed by Falling Prices

With tax burdens lower, many products will see direct cost reductions. Already, automakers like Maruti Suzuki have announced price cuts (e.g. shifting from 28 % to 18 %) to pass on benefit to customers.

Consumers respond strongly to lower prices the elasticity of demand tends to favor more buying in discretionary goods, appliances, automobiles, electronics, fashion, etc.

Sectors that benefit most: consumer goods, retail, e-commerce, consumer durables, automobiles, lifestyle goods – these are likely to see a sharp uptick in volumes as lower taxes stimulate consumption.

4. Flow of money: from tax reduction to wider circulation

Here's a simplified "money-flow" view of how GST 2.0 recharges the economy:

1. Government cuts tax rates net price to consumer falls
2. Consumers spend more on more goods or better goods
3. Producers Boost Production & hire labor incomes rise
4. Incomes get spent again further consumption
5. Businesses gain; formal sector expands investment picks up
6. Government may lose revenue short term, but via growth, buoyant collection, and broader base, revenue recovers in medium term

Indeed, estimates suggest that consumption may get a boost of ₹1.98 lakh crore under the new structure, according to SBI research.

Government expects some revenue loss initially but the hope is that growth dividends offset those losses later.

5. Challenges, risks & balancing act

While the upside is strong, some challenges remain:

• Revenue shortfall:

The government must manage deficits if collections dip sharply in the early phase.

• Ensuring pass-through:

Producers must indeed pass on the tax cut to consumers, not pocket margins.

• Monitoring and compliance:

Simplification helps, but abuse must be prevented via good oversight.

• Longer term stability:

Rates must remain predictable to give confidence to investors.

Conclusion

GST 2.0 is more than a tax reform; it is a growth lever. By putting more money in hands of consumers, improving business liquidity, and stimulating sales, it has the potential to create a virtuous cycle of demand, production, and income. If executed well, the revised GST in 2025 can become a structural support for India's next phase of economic expansion turning tax cuts into growth, and liquidity into prosperity.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor



Insurers Gear Up for EV Boom with Innovative Performance-Linked Battery Policies

New Covers Target Battery Degradation Risks as EVs Hit 20 Lakh Sales Milestone in last year

Bhopal: As electric vehicles (EVs) accelerate their takeover of Indian roads, crossing 65 lakh units in circulation and clocking 20 lakh sales in 2024 alone, insurers are racing to innovate motor policies tailored to the sector's unique challenges. At the forefront is the battery, which can account for up to 60% of an EV's cost and poses risks like performance degradation, accidental damage, and fire hazards that traditional internal combustion engine (ICE) covers simply don't address.

Industry executives revealed that performance-linked battery insurance is emerging as a game-changer. Unlike standard warranties, these policies would activate claims if a battery underperforms, say, falling below 70% capacity within its guaranteed lifespan, offering repairs or full

replacements. "We're studying global models from Asia and Europe to launch these in India soon," said a senior official from a leading general insurer. Current EV policies already include add-ons for battery protection against accidents or floods, but performance guarantees could slash out-of-pocket expenses, which often run into Rs 4-10 lakh for high-end models like those from Tesla.

This shift comes amid surging demand, fueled by government incentives like the FAME scheme and PLI for advanced batteries. Insurers such as Bajaj Allianz, ACKO, and Tata AIG have rolled out EV-specific products with 15% discounts on third-party premiums, alongside covers for charging equipment and roadside assistance for battery issues. However, premiums remain 20-30% higher than ICE

vehicles due to elevated repair costs and specialized parts. Experts hail the move as crucial for boosting adoption, especially in urban hubs where EV penetration exceeds 30%. "Battery-as-a-service models from automakers could integrate seamlessly, lowering upfront costs," noted Animesh Das, Chief Underwriting Officer at ACKO. Yet, challenges persist: limited repair networks and data on long-term degradation mean policies will evolve iteratively.

With India's EV market projected to hit 10 million units by 2030, these innovations not only mitigate risks but also align with the green mobility push, potentially saving consumers billions while greening the insurance landscape.

Jio-BlackRock Unveils India's First AI-Driven Equity Fund: Entry at Just Rs 500

Flexi Cap Scheme Blends BlackRock's SAE Strategy with Human Expertise for Retail Investors

Mumbai: Jio-BlackRock Mutual Fund, the 50:50 joint venture between Jio Financial Services and global giant BlackRock, has launched India's pioneering AI-powered active equity fund—the JioBlackRock Flexi Cap Fund. The New Fund Offer (NFO) opened on September 23 and runs until October 7, marking a milestone in democratizing advanced investment tools for retail investors.

This open-ended flexi-cap scheme invests 65-100% in equities across large, mid, and small-cap stocks, with up to 35% in debt and money market instruments, and 0-10% in REITs/ InvITs. What sets it apart is BlackRock's proprietary Systematic Active Equity (SAE) model, leveraging AI, machine learning, and alternative data like consumer transactions and search trends analyzed via the Aladdin platform to scan nearly 1,000 Indian companies. Fund managers Tanvi Kacheria and Sahil Chaudhary blend these insights with human judgment for diversified, risk-spread portfolios benchmarked against the Nifty 500 TRI. Accessibility is key: Retail investors can start with a minimum Rs 500 lump-sum investment or SIP (with six installments mandatory, in multiples of Re 1 thereafter). No entry or exit loads apply, and the direct growth plan keeps the Total Expense Ratio (TER) at a cap of 2.25%. Available exclusively on the Paytm Money app, it targets long-term capital appreciation amid India's booming equity market.

"This fusion of AI and expertise uncovers smarter opportunities, making institutional-grade strategies available to every Indian," said a JioBlackRock spokesperson. Analysts praise the low entry barrier as a booster for financial inclusion, potentially attracting millions in a Rs 50 lakh crore mutual fund industry. With no upper investment limit, it's ideal for those seeking growth through diversified equity exposure.

Term & Health Insurance just got

18% CHEAPER!



Still waiting to buy insurance?

There's no better time than now

Not sure which one to choose? Let me guide you



Vision Invest Tech Private Limited

ARN: 10613 | AMFI Registered Mutual Fund Distributor

(+91) 7389912025 | visionadvisorymkt@gmail.com



Bajaj Electricals Secures Morphy Richards Brand Rights in South Asia for Rs 146 Crore

Strategic Move to Strengthen Consumer Durables Portfolio Amidst Growing Regional Demand

Bhopal: In a significant expansion of its consumer durables business, Bajaj Electricals Ltd. has announced the acquisition of exclusive brand rights for Morphy Richards in South Asia for Rs 146 crore. The deal, finalized with Hong Kong-based Group 3 Limited, the global owner of the iconic British brand, will grant Bajaj Electricals perpetual rights to manufacture, market, and distribute Morphy Richards small appliances across India, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan, and the Maldives.

This acquisition comes at a pivotal time for Bajaj Electricals, which has been aggressively diversifying its product lineup to capture a larger share of the burgeoning South Asian market for home appliances. Morphy Richards, renowned for its premium kitchen and small home appliances like toasters,

kettles, irons, and vacuum cleaners, aligns seamlessly with Bajaj's existing portfolio of fans, lights, and mixers. The move is expected to enhance Bajaj's premium segment offerings, leveraging Morphy Richards' strong brand equity and design heritage dating back to 1933.

Bajaj Electricals' Managing Director, Shekhar Bajaj, expressed enthusiasm about the partnership, stating, "This acquisition marks a transformative step for us. Morphy Richards' legacy of innovation and quality will complement our strengths in distribution and manufacturing, enabling us to deliver world-class products to South Asian consumers. We anticipate a significant revenue boost from this synergy."

Financial analysts view the deal positively, noting that the Rs 146 crore investment is strategically priced, with potential for quick returns given the region's 8-10% annual growth in consumer durables.

The transaction is subject to customary approvals and is slated for completion by the end of Q4 FY2025. This development underscores Bajaj Electricals' commitment to inorganic growth, following its recent acquisitions and joint ventures.

As competition intensifies from global players like Philips and local rivals, this brand infusion positions Bajaj Electricals to innovate and expand its market penetration, potentially driving its market capitalization higher in the coming quarters.



Offline Smartphone Sales Crash 40% as Shoppers Eye Online Festive Deals

Traditional Retailers Face Squeeze from Flipkart, Amazon's Aggressive Discounts and Exclusive Stock

Bhopal: is witnessing a dramatic shift, with offline smartphone sales dropping nearly 40% over the past 10 days, according to industry executives and market trackers. The steep decline comes as consumers hold back purchases in anticipation of blockbuster e-commerce sale events, where deep discounts on premium devices from brands like Apple and Samsung are expected to steal the show.

Flipkart kicked off its Big Billion Days sale at midnight on Monday, closely followed by Amazon's Great Indian Festival, offering up to 60% off on smartphones, no-cost EMI options, and bundle deals. These events have prompted shoppers to delay brick-and-mortar buys, exacerbating the woes of over 150,000 offline retailers represented by the All-India Mobile

Retailers Association (AIMRA). "Consumers are savvy; they're waiting for the online frenzy where prices drop significantly," said Kailash Lakhani, AIMRA chairman. He highlighted that offline stores simply can't match the aggressive pricing, leading to empty showrooms and unsold inventory.

Adding fuel to the fire, major brands have funnelled substantial stock to digital platforms. Apple and Samsung each allocated around 2 million units for the initial sale phase, while other brands contributed 3-4 million, per industry estimates. This preferential treatment underscores the growing dominance of e-commerce, which now accounts for over 50% of smartphone sales in India, up from 35% last year.

The timing couldn't be worse for offline

retailers who are already grappling with rising operational costs and a GST rate unchanged at 18% for mobiles unlike reductions for other electronics like TVs and ACs. Retailers report footfall down by half, with mid-range and entry-level phones hit hardest. "This seasonal dip is deeper than usual; we're seeing a structural shift," noted an executive from a leading chain.

While e-tailers celebrate projected sales surges potentially crossing Rs 50,000 crore during the festive window traditional retailers are calling for government intervention to level the playing field, including better credit access and anti-predatory pricing norms. As the digital divide widens, the offline sector's resilience hangs in the balance, threatening jobs and local economies.

Delhi HC Orders Patanjali to Trim 'Disparaging' Chyawanprash Ads Targeting Dabur

Division Bench Modifies Single-Judge Order, permits 'Ordinary' Claim but Bans Herb Count Reference

New Delhi: In a fresh twist to the ongoing legal tussle between Ayurvedic giants Patanjali Ayurved and Dabur India, the Delhi High Court has directed Patanjali to excise specific portions of its Chyawanprash advertisements deemed disparaging. The division bench, comprising Justices Hari Shankar and Om Prakash Shukla, allowed the company to retain the phrase "why settle for ordinary Chyawanprash" as permissible "puffery" but mandated the removal of the subsequent line referencing "made with 40 herbs," which implicitly targeted Dabur's flagship product.

This ruling modifies a July 3 single-judge order by Justice Mini Pushkarna, who had restrained Patanjali from airing ads that claimed "no other manufacturer has the knowledge to prepare Chyawanprash" per ancient Ayurvedic texts. Dabur, holding over 60% market share in

Chyawanprash, argued the campaign constituted specific disparagement against its 40+ herb formulation and generic denigration of the entire category. The ads, featuring yoga guru Baba Ramdev, portrayed rivals as lacking Vedic expertise, misleading consumers and eroding trust.

Patanjali's counsel assured the court of compliance, emphasizing the ads promote their "Special Chyawanprash" without seeking to revive barred elements. "We don't think 'ordinary' will deter people from Dabur," the bench remarked, distinguishing it from overt negativity. The order came on Patanjali's appeal, where the court had earlier warned of costs for "luxury litigation."

Dabur hailed the decision as a victory for fair advertising, stating it protects consumers from false superiority claims. Patanjali, however, views the modified ads

as a boost to authentic Ayurvedic marketing. The case, underscoring rising scrutiny on comparative ads in FMCG, is set for further hearing. Industry watchers say this could set precedents for herbal product promotions, balancing innovation with ethical boundaries in a Rs 5,000-crore Chyawanprash market



CCI Approves Apollo Hospitals' Multi-Layered Group Restructuring, Boosting Omnichannel Expansion

Healthco and Keimed Mergers into Healthtech Clear Path for Separate Listing of Pharmacy and Digital Arms

New Delhi: The Competition Commission of India (CCI) has given the green light to Apollo Hospitals Enterprise's ambitious restructuring plan involving its key group entities, marking a pivotal step toward unlocking shareholder value and accelerating growth in the healthcare sector. The approval, announced on September 23, encompasses mergers and demergers aimed at streamlining operations for Apollo Healthco, Keimed Pvt Ltd, and Apollo Healthtech Ltd.

Under the plan, Apollo Healthco the digital health and pharmacy arm and Keimed, the private label drug firm, will merge into Apollo Healthtech, creating a unified entity focused on omnichannel healthcare services. This consolidation will pave the way for a separate listing of these businesses on stock exchanges within

18-21 months, as initially outlined in June 2025.

Apollo Hospitals aims to leverage this structure to target Rs 25,000 crore in revenue by fiscal 2027, driven by expanded digital platforms, pharmacy chains, and telemedicine services.

The restructuring is designed to enhance operational efficiency and foster innovation in a competitive market, where digital health adoption has surged post-pandemic. "This approval validates our strategy to create focused entities that can scale independently while synergizing with our core hospital business," a company spokesperson stated, highlighting the potential for greater investor access to high-growth segments.

Analysts view the move positively, noting

it could improve Apollo's valuation multiples amid India's booming Rs 10-lakh crore healthcare industry. The plan aligns with broader trends of corporate unbundling to capitalize on specialized growth areas. With CCI's nod, Apollo is now poised to execute the swaps and infusions, potentially injecting fresh capital into its ecosystem. This development underscores the regulator's role in facilitating value-creating reforms without compromising competition.



Fortis Healthcare Accelerates Obesity Clinic Rollout Amid Surging Weight-Loss Drug Demand

CEO Raghuvanshi Unveils Plans for 13 New Centers, Backed by Rs 7,000 Crore Hospital Expansion

New Delhi: Fortis Healthcare is ramping up its focus on obesity management, planning to launch 13 additional specialized clinics across India to capitalize on the explosive growth in weight-loss therapies. CEO Ashutosh Raghuvanshi announced the initiative, highlighting the rising demand driven by GLP-1 agonists like semaglutide (Ozempic) and tirzepatide, which have transformed global and Indian markets for obesity treatment.

The expansion builds on five existing clinics already operational in Delhi, Gurgaon, Mumbai, and Bengaluru, offering multidisciplinary care involving endocrinologists, bariatric surgeons, nutritionists, dieticians, and psychologists. "With obesity rates climbing to over 20% in urban India, we're positioning Fortis as a leader in holistic weight management," Raghuvanshi told

Reuters. The new facilities will integrate medical, surgical, and lifestyle interventions, aiming to address not just weight loss but long-term health outcomes.

This move aligns with Fortis's broader Rs 7,000 crore investment over the next four years to enhance hospital capacities in key cities like Bengaluru and Mumbai. The company anticipates the obesity segment to contribute significantly to its revenue, projected to hit Rs 25,000 crore by FY27, fueled by increasing awareness and affordability of therapies. Analysts note that India's obesity drug market could reach \$1 billion by 2030, with domestic players like Zydus Lifesciences ramping up production.

Raghuvanshi emphasized ethical practices, warning against unregulated use of weight-loss drugs. "Our clinics will prioritize evidence-based protocols to

ensure patient safety," he added. As lifestyle diseases escalate with 135 million obese adults in India Fortis's strategy underscores a shift toward preventive healthcare. Investors welcomed the news, with Fortis shares rising 2% in early trade. This expansion not only meets market needs but also reinforces Fortis's commitment to tackling India's public health challenges head-on.



Tata 1mg Eyes \$200M Funding Boost Amid Valuation Tug-of-War with Global Investors

Novo Holdings, CPPIB, Permira, and ChrysCapital in Talks, But Push for Down Round from \$1.25B Tag

Mumbai: Tata Digital's e-pharmacy arm, Tata 1mg, is gearing up for a significant capital infusion of up to \$200 million (Rs 1,700 crore) to fuel its expansion in India's booming online healthcare market. Sources close to the development reveal that high-profile investors, including Novo Holdings the investment arm of Novo Nordisk Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), global buyout firm Permira, and Indian PE player ChrysCapital, have expressed keen interest in the round.

The funding comes at a crucial juncture for the loss-making platform, which seeks to enhance its digital health services, logistics, and diagnostics amid fierce competition from PharmEasy and Apollo 24/7. Valued at \$1.25 billion in its 2022 Series E round, Tata 1mg's aggressive growth strategy has driven user engagement, but investors are balking at the premium, proposing a more grounded

\$750-800 million valuation. "This reflects market realities in a maturing e-pharma space, where profitability remains elusive," noted an industry analyst. Complicating negotiations, some suitors are angling for board seats and veto rights, which Tata Sons is reportedly resisting to maintain control. If talks stall, Tata may inject \$75 million internally via a down round, with the balance from external sources. This infusion aligns with broader capital raises across Tata Digital, including for Big Basket.

Novo Holdings' involvement is particularly intriguing, given its expertise in obesity and diabetes therapeutics, potentially synergizing with 1mg's chronic care focus. CPPIB and Permira bring institutional heft, while ChrysCapital adds local market savvy. The deal, if sealed, could propel Tata 1mg toward unicorn revival and solidify its 15% market share in a sector projected to hit \$10 billion by

2030.

Tata Sons and the investors declined immediate comment, but the buzz underscores investor confidence in India's digital health pivot, despite valuation headwinds.



WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1

Anil Bhardwaj

Technical Head

anil.stockcare@gmail.com

- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24655	25813	25572	25113	24872	24413	24172	23713
BANK NIFTY	54389	56617	56141	55265	54789	53913	53437	52561
SENSEX	80426	84137	83357	81892	81112	79647	78867	77402
FINNIFTY	25985	27160	26910	26447	26197	25734	25484	25021
MIDCAP	12563	13691	13458	13011	12778	12331	12098	11651
ACC	1825	1990	1954	1889	1853	1788	1752	1687
AXISBANK	1154	1216	1195	1174	1153	1132	1111	1090
ABCAPITAL	280	314	307	293	286	272	265	251
BHARTIARTL	1915	2004	1985	1950	1931	1896	1877	1842
BHEL	231	251	246	239	234	227	222	215
BIOCON	339	392	381	360	349	328	317	296
CDSL	1473	1672	1627	1550	1505	1428	1383	1306
DATAPATTERN	2660	3093	2995	2828	2730	2563	2465	2298
ESCORTS	3526	3916	3838	3682	3604	3448	3370	3214
EICHERMOTOR	7035	7318	7220	7127	7029	6936	6838	6745
FEDERAL BANK	192	206	203	197	194	188	185	179
GRINFRAPROJECT	1250	1413	1377	1314	1278	1215	1179	1116
HDFCBANK	945	994	982	964	952	934	922	904
HCLTECH	1395	1489	1469	1432	1412	1375	1355	1318
HINDUNILVR	2512	2653	2620	2566	2533	2479	2446	2392
HAL	4735	5103	5022	4878	4797	4653	4572	4428
HYUNDAI	2633	3067	2978	2806	2717	2545	2456	2284
IOC	145	153	151	148	146	143	141	138
ICICIBANK	1363	1449	1430	1396	1377	1343	1324	1290
INFY	1452	1570	1542	1497	1469	1424	1396	1351
ITC	405	424	418	411	405	398	392	385
KOTAKBNK	1994	2099	2076	2035	2012	1971	1948	1907
LICHOUSING	563	616	606	584	574	552	542	520
LT	3743	4002	3898	3821	3717	3640	3536	3459
LUPIN	1923	2147	2098	2011	1962	1875	1826	1739
MARUTI	16307	17224	16830	16568	16174	15912	15518	15256
M&M	3400	3876	3777	3589	3490	3302	3203	3015
MGL	1242	1433	1391	1317	1275	1201	1159	1085
MAZGAONDOC	2839	3231	3146	2992	2907	2753	2668	2514
PFC	398	430	423	410	403	390	383	370
RECLTD	368	407	398	383	374	359	350	335
RELIANCE	1379	1450	1430	1405	1385	1360	1340	1315
SBIN	857	903	892	874	863	845	834	816
SUNPHARMA	1585	1754	1706	1645	1597	1536	1488	1427
SHRIRAMFINANCE	606	661	649	628	616	595	583	562
TITAN	3333	3603	3540	3436	3373	3269	3206	3102
TCS	2905	3259	3182	3044	2967	2829	2752	2614
TATAMOTORS	674	761	737	705	681	649	625	593
UPL	646	726	710	678	662	630	614	582
VALIENT	332	383	372	352	341	321	310	290
WIPRO	237	265	258	248	241	231	224	214

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

तमिलनाडु में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की 1,156 करोड़ की निवेश योजना: इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

थूथुकुदी में 60 एकड़ फैसिलिटी से 2,000 नौकरियां, सैक्स से एडिबल अॅयल तक उत्पादन

चेन्नई: रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (आरसीपीएल), रिलायंस रिटेल की एफएमसीजी शाखा, तमिलनाडु में 1,156 करोड़ रुपये का निवेश कर एक एकीकृत विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। यह सुविधा थूथुकुदी जिले के सिपाकॉट अलीकुलम इंडस्ट्रियल पार्क में 60 एकड़ क्षेत्र में बनेगी, जहां सैक्स, बिस्किट, मसाले, आटा और खाद्य तेल जैसे उत्पादों का उत्पादन होगा। राज्य उद्योग मंत्री टीआरबी राजा ने सोमवार को एक्स पर इसकी घोषणा की, इसे तमिलनाडु की औद्योगिक प्रगति का एक और मील का पथर बताया।

राजा ने लिखा, "एक और एफएमसीजी दिग्गज ने तमिलनाडु को चुना! रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड अपनी अगली बड़ी इकाई के लिए तमिलनाडु पर दांव लगा रही है। सिपाकॉट अलीकुलम इंडस्ट्रियल पार्क में 1,156 करोड़ का निवेश होगा।" यह निवेश अगले पांच वर्षों में स्थानीय स्तर पर 2,000 नौकरियां पैदा करेगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। रिलायंस का यह कदम दक्षिण भारत में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है, जहां एफएमसीजी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है।

कंपनी के इस विस्तार से क्षेत्रीय उत्पादों पर जोर मिलेगा, जो उपभोक्ता पसंद को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाएंगे। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में टीएन राइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉन्सलेन्स में 32,553 करोड़ के निवेश के 41 एमओयू साइन किए हैं, जिसमें कोविन शिपयार्ड और मझगांव डॉक जैसे पीएसयू भी शामिल हैं। यह निवेश राज्य को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

विशेषज्ञों का मानना है कि रिलायंस का यह कदम एफएमसीजी बाजार में प्रतिस्पर्धा को तीव्र करेगा और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई में कंपनी का यह प्रयास भारत की 'मेक इन इंडिया' पहल को भी बढ़ावा देगा।